भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1537

09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कपास और सोयाबीन से संबंधित विशेष परियोजना

1537. श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत कपास और सोयाबीन से संबंधित विशेष परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कपास और सोयाबीन से संबंधित विशेष परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित क्लस्टरों और जिलों, विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र में, उन क्लस्टरों का ब्यौरा क्या है जहाँ कपास के लिए उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) और निकट अंतराल रोपण प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा सोयाबीन किसानों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने परियोजना संबंधित उपायो के माध्यम से कपास और सोयाबीन उत्पादकता में सुधार का मूल्यांकन करने हेतु विशिष्ट परियोजना का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) [पूर्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)] के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से कपास पर एक विशेष परियोजना 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों को लक्षित करना-कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के

कार्यान्वयन हेतु आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर को वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (नवंबर, 2025 तक) के लिए क्रमशः 2093.42 लाख रुपये, 2548.94 लाख रुपये और 1508.08 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सहित प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में किया जा रहा है।

(ख) एवं (ग): कपास पर विशेष परियोजना के अंतर्गत शामिल जिलों और क्लस्टरों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	संपूर्ण भारत		महाराष्ट्र		महाराष्ट्र में एचडीपीएस		महाराष्ट्र में निकट अंतराल (सीएस)	
	जिले	क्लस्टर	जिले	क्लस्टर	जिले	क्लस्टर	जिले	क्लस्टर
2023-24	61	373	16	74	9	40	16	66
2024-25	65	461	16	115	11	62	15	105
2025-26	65	412	17	121	10	60	15	106

(घ): सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की दिशा में प्रयास करने के लिए 3 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दे दी है जिसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र सहित देश भर में वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक की सात वर्षों की अवधि में किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन का उद्देश्य सोयाबीन, रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, अरंडी और अलसी जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, साथ ही कपास के बीज, राइस ब्रान, मक्का का तेल और ट्री बोर्न ऑयल जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह, निष्कर्षण और पुनर्प्राप्ति की दक्षता को बढ़ाना है।

(ङ): कपास पर विशेष परियोजना के तहत पारंपरिक पद्धति की तुलना में उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) प्रौद्योगिकी और क्लोजर स्पेसिंग (सीएस) प्रौद्योगिकी के प्रदर्शित भूखंडों में कपास की औसत उत्पादकता में वृद्धि वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 30.40% और 39.15% और 2024-25 के दौरान क्रमशः 39.81% और 32.45% हुई है।

*****